

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1479 का उत्तर

मुंबई में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाली रेलगाड़ियां

1479. श्री रविंद्र दत्ताराम वाङ्कर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में मुंबई की लोकल रेलगाड़ियों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर चर्चगेट से विरार, वी.टी. से ठाणे और कल्याण से कर्जत तक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाली रेलगाड़ियां शुरू करने का विचार है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित की जानी है और यह कार्य कब तक शुरू किया जाना प्रस्तावित है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है;
- (घ) क्या सरकार का मुंबई में लोकल रेलगाड़ियों की तर्ज पर भविष्य में लाखों यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने हेतु मेट्रो ट्रेनें चलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

मुंबई में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाली रेलगाड़ियों के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर के अतारांकित प्रश्न सं. 1479 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): दैनिक यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई क्षेत्र में फिलहाल वातानुकूलित-ईएमयू सहित उपनगरीय सेवाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में, पश्चिम रेलवे पर 1394 सेवाएं चलती हैं। जिनमें 96 वातानुकूलित सेवाएं शामिल हैं। मध्य रेलवे भी 1810 सेवाएं परिचालित करती है, जिनमें 66 वातानुकूलित सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, नई गाड़ियां चलाना और उनके भार बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है। यात्रियों की भावी मांगों को पूरा करने के लिए मुंबई उपनगरीय गलियारों पर भीड़-भाड़ से बचने के लिए भारतीय रेल 8,087 करोड़ रुपये की लागत वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II, 10,947 करोड़ रुपये की लागत वाली एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत वाली एमयूटीपी-IIIए के माध्यम से मुंबई में उपनगरीय नेटवर्क को सुदृढ़/संवर्धित कर रही है। इन परियोजनाओं में मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित रेल लिंक शामिल हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन (30 कि.मी.)	919
2	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 कि.मी.)	826
3	विरार-दहाणु रोड की तीसरी एवं चौथी लाइन (64 कि.मी.)	3587
4	सीएसटीएम-कुर्ला पांचवीं एवं छठी लाइन (17.5 कि.मी.)	891
5	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 कि.मी.)	2782
6	एरोली-कलवा (एलीवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (3.3 कि.मी.)	476
7	बोरीवली-विरार 5वीं एवं 6ठी लाइन (26 कि.मी.)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच 4थी लाइन (32 कि.मी.)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 कि.मी.)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं का वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

वित्त वर्ष 2020-24 के लिए एमयूटीपी परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार आबंटित धनराशि क्रमशः 555 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए, 577.50 करोड़ रुपए और 1100.01 करोड़ रुपए है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना/ओं की साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं।
